PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Mail Today, Delhi
Monday 11th May 2015, Page: 26
Width: 25.95 cms, Height: 12.74 cms, a4r, Ref: pmin.2015-05-11.31.67

CRAFT IS OUT OF THE BAG

IF AN affluent Indian were to go shopping for lifestyle products such as a handbag or sunglasses, the tendency is to invariably buy an international brand such as Michael Kors or Coach. Dilip Kapur, founder of ₹160-crore, home-grown Hidesign, is on a mission to tell the world what Hidesign stands for. He is doing an Icon Exhibition across cities to tell consumers about his brand's journey since 1978. "Not many know that Hidesign bags are completely handcrafted unlike most global brands, which are mass produced. I don't believe in line production," he recently said.

PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Dainik Jagran, Delhi
Monday 11th May 2015, Page: 8
Width: 34.88 cms, Height: 48.82 cms, a3, Ref: pmin.2015-05-11.34.44

भूमि अधिग्रहण बिल वक्त की मांग

2013 के कानून में किसान विरोधी जितनी बातें हैं, विकास विरोधी जो प्रावधान हैं, अफसरशाही को बढ़ावा देने के लिए जो व्यवस्थाएं हैं, उनको ठीक करके किसान एवं देश को संरक्षित करना चाहिए। हम जो सुधार लाए हैं, अगर वो नहीं लाते तो किसानों के लिए सिंचाई योजनाएं असंभव बन जातीं।

स्वास्थ्य सेवाओं का आधुनिकीकरण एवं फैलाव-देश की महिला, बच्चे एवं बुजुर्ग गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य सेवाओं से आज भी वंचित हैं। हम कब तक इस परिस्थिति को चलाएंगे।

देश को स्वच्छ बनाने की बात हो, स्कूलों में शौचालय बनाने की बात हो-यह सरकार के साथ-साथ जनभागीदारी का काम है, लेकिन जरूरी है।

इन सारे कामों के लिए हमने अपने लिए और देश के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम निश्चित किया है। इन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए हम कमर कस कर काम कर रहे हैं। देशवासियों के आशीर्वाद से हम देश को इन ऐतिहासिक समस्याओं से संपूर्ण रूप से निकालने में अवश्य सफल होंगे।

अब गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने का सार्थक प्रयास हो रहा है। गरीबी से मुक्ति दिलाने के लिए एक के बाद एक महत्वपूर्ण आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक कदम उठाए जा रहे हैं। उसके कारण गरीबी के नाम पर राजनीति करने वालों का चेहरा बेनकाब हो गया है। उनको चिंता होने लगी है कि जिन गरीबों को हमने भ्रमित करके 60 सालों तक कब्जे में रखा, वे अगर सत्य जान जाएंगे और गरीबी से बाहर आएंगे तो राजनीति का मृत्युघंट बज जाएगा। वो कहते हैं न, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, वो वाला खेल चल रहा है।

सरकार कुछ कर नहीं पा रही है, क्या एक साल में ऐसी धारणा नहीं बनी है?

-(अर्थपूर्ण तरीके से हंसते हैं) चुनाव के पूर्व के इन दिनों को याद कीजिए। अपना खुद का अखबार निकाल लीजिए। उसमें क्या भरा पड़ा था। अब गत एक वर्ष के अखबार निकाल लीजिए। लोकसभा चुनाव से पहले आप देखेंगे दैनिक जागरण इन खबरों से भरा पड़ा होता था कि ये घोटाला, वो घोटाला... ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ... इस बात का पता नहीं, उस बात का पता नहीं।

अब अभी के अखबार देखिए क्या छपा है? आपदा आई नेपाल में और भारत सरकार पहुंच गई। यमन में हम पहुंचे, कश्मीर की त्रासदी हुई तो हम वहां थे। कोई घोटाला नहीं है। ओले गिरे तो सारे मंत्री खेतों में पहुंच गए। सबको दिख रहा है। पहले चर्चा होती थी 1.74 लाख करोड़ का कोयला घोटाला। इस बार गौरव से खबरें आ रही हैं कि दो लाख करोड़ रुपये से ज्यादा सिर्फ दस फीसद कोयला ब्लॉक की नीलामी से आ गए। तब खबरें थीं कि महंगाई बढ़ रही। अब आती है कि इतनी कम हो रही है। यही समाचार आ रहे हैं। पहले दुनिया के देशों में विदेश मंत्री जाते थे और दूसरे देश का भाषण पढ़कर आते थे। अब दुनिया के देश हिंदुस्तान की बात बोलने लगे हैं। बिजली उत्पादन पर आएं तो पिछले 30 साल में इतना ग्रोथ कभी नहीं हुआ। सड़क निर्माण पर आएं तो पिछले दस सालों में प्रति दिन दो किलोमीटर सड़क बनने का औसत था, जो अब 10 किलोमीटर से ज्यादा पहुंच गया है। एफडीआइ और विदेशी पर्यटक के आने जैसे हर क्षेत्र में अच्छी खबरें हैं, आप कोई भी विषय ले लीजिए। (फिर थोड़ा रुककर...) मोदी के राज में समय पर आफिस जाना पड़ता है। यही आलोचना है।

भविष्य के लिहाज से देश के सामने मुख्य चुनौतियां क्या हैं और इनसे पार पाने के लिए कितना समय चाहिए?

-आपने हमारे इस साल का बजट पत्र देखा होगा। देश की ऐतिहासिक समस्याओं को 5-7 सालों में दूर करने का हमने बीड़ा उठाया है। वह चाहे गरीबों को घर देने की बात हो, पानी, बिजली, सड़क की सुविधाएं पूर्ण करने की बात हो, कोई कारण नहीं है कि देश का एक बड़ा तबका इन सारी सुविधाओं से वंचित रहे। शिक्षा की बात हो। डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया से देश को प्रौद्योगिकी और हुनर देने की बात हो- हम एक युवा देश हैं और आधुनिक युग की जरूरतों के मुताबिक देश के नौजवानों को रोजगार के साथ-साथ विश्व के साथ आंख में आंख मिलाकर काम कर सकें, इस प्रकार तैयार करना जरूरी है।

मगर सरकार को गरीब विरोधी ठहराने में विपक्ष कामयाब दिख रहा है। भूमि अधिग्रहण पर कांग्रेस आक्रामक है, लगता है कहीं कोई कमी रह गई?

-(पंचवटी में अचानक उठे मोरों के कलरव को सुनकर हम सभी थोड़ी देर चुप हो जाते हैं...फिर वह सहज भाव से कहते हैं) इसका पूरा इतिहास समझिए। भूमि अधिग्रहण विधेयक पर 120 साल बाद विचार हुआ। इतने पुराने कानून पर विचार के लिए 120 घंटे भी लगाए थे क्या? नहीं लगाए थे। और उसमें सिर्फ कांग्रेस पार्टी दोषी है, ऐसा नहीं है। हम भी भाजपा के तौर पर दोषी हैं, क्योंकि हमने साथ दिया था। चुनाव सामने थे और सत्र पूरा होना था, इसलिए जल्दबाजी में निर्णय हो गया। बाद में हर एक राज्य को लगा कि ये तो बड़ा संकट है। मुझे सरकार बनने के बाद करीब-करीब सभी मुख्यमंत्रियों ने एक ही बात कही कि भूमि अधिग्रहण विधेयक ठीक करना पड़ेगा, वरना हम काम नहीं कर पाएंगे। हमारे पास लिखित चिट्ठियां हैं।

जैसे सियासी हालात बने, उससे नहीं लगता कि भूमि अधिग्रहण विधेयक पर किसानों को समझाने में आपकी सरकार विफल रही है?

-आपकी बात सही है। किसी न किसी राजनीतिक स्वार्थ के माहौल के कारण सत्य पहुंचाने में अनेक रुकावटें आई हैं। ये भ्रम फैलाने में हमारे विरोधी सफल हुए हैं कि भूमि अधिग्रहण विधेयक आने के बाद कॉरपोरेट घरानों के लिए जमीन ले ली जाएगी। जबकि हकीकत यह है कि कॉरपोरेट के लिए जमीन देने के मामले में हमने 2013 के विधेयक में मौजूद प्रावधान को रत्ती भर भी नहीं बदला है। हमारे सुधारों के तहत किसी भी उद्योग घराने या कॉरपोरेट को कोई जमीन नहीं दी है और न ही ऐसा कोई इरादा है। हमने जो सुधार सूचित किए हैं उनसे एक इंच जमीन भी उद्योग को मिलने में सुविधा नहीं होगी। ये सरासर झूठ है लेकिन चलाया जा रहा है। भूमि अधिग्रहण विधेयक में बदलाव करना, ये न भाजपा का एजेंडा और न ही मेरी सरकार का एजेंडा है। करीब सभी राज्य सरकारों की तरफ से इसमें बदलाव का आग्रह था।

जल्दबाजी में बने हुए 2013 के कानून में किसान विरोधी जितनी बातें हैं, विकास विरोधी जो प्रावधान हैं, अफसरशाही को बढ़ावा देने के लिए जो व्यवस्थायें हैं उनको ठीक करके किसान एवं देश को संरक्षित करना चाहिए। हम जो सुधार लाए हैं, अगर वो नहीं लाते तो किसानों के लिए सिंचाई योजनाएं असंभव बन जातीं। गांवों में किसानों को पक्के रास्ते नहीं मिलते। गांवों में गरीबों के लिए घर नहीं बना पाते। इसलिए गांव के विकास के लिए, किसान की भलाई के लिए कानून की जो कमियां थीं वो दूर करनी जरूरी थीं और जिसकी राज्यों ने मांग की थीं। हमने किसान हित में एक पवित्र एवं प्रामाणिक प्रयास किया है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में झूठ बेनकाब होगा और भ्रम से मुक्ति मिलेगी।

इस संवेदनशील मुद्दे पर भाजपा और सरकार के कई नेता भी हिचक रहे थे, फिर भी भूमि अधिग्रहण विधेयक पर सरकार ने सियासी खतरा लिया?

-जैसा मैंने कहा कि भूमि अधिग्रहण विधेयक में बदलाव करना, यह न भाजपा का एजेंडा है और न ही मेरी सरकार का। सभी मुख्यमंत्री तो इसमें बदलाव चाहते ही थे। इसकी बीच एक घटना ऐसी घटी कि कांग्रेस के वरिष्ठ और अनुभवी नेता रहे जेबी पटनायक असम के राज्यपाल थे। मैं राज्य के दौरे पर गया तो राजभवन में उन्होंने मुझसे दो बातें कहीं। पहली तो कि मोदी जी मेरी एक इच्छा है कि एक माह के बाद मेरा कार्यकाल खत्म हो रहा है, मेरे जाने से पहले उत्तराधिकारी आ जाए। दूसरी बात उन्होंने ओडिशा के मुख्यमंत्री के तौर पर अपने प्रशासनिक अनुभव के नाते कही। उन्होंने कहा कि हम या हमारे लोग परिपक्वता के अभाव में जो भूमि अधिग्रहण विधेयक लाए हैं, इसे मेहरबानी करके खत्म करो। इससे देश नहीं चलेगा। मैं वर्षों तक ओडिशा का मुख्यमंत्री रहा हूं, मेरा अनुभव कहता है कि ऐसा नहीं चल सकता। वह कांग्रेस के बड़े नेता और अनुभवी व्यक्ति थे।

रोजगार व अन्य मुद्दों पर भी आपकी सरकार सवालों के घेरे में है?

-सरकार में रहते हुए विपक्ष ने स्वयं कुछ नहीं किया। जिन लोगों को पांच-पांच, छह-छह दशक तक इस देश में राज करने का मौका मिला, उन लोगों की कमजोरी है कि वे सत्ता भी नहीं पचा पाए। अब आज घोर पराजय के बाद पराजय भी नहीं पचा पा रहे हैं। हम भली-भांति जानते हैं कि जातिवाद का जहर, संप्रदायवाद का जहर, गरीबों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने की परंपरा इस देश ने लंबे अरसे से देखी है।

हम जिन संकल्पों को लेकर चल रहे हैं, उनके तहत आने वाले 5-7 सालों में देश की तस्वीर अलग होगी और यही बात उनको सोने नहीं दे रही है। इसलिए हमारे कामों में बाधा डालने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अच्छी भावनाओं के साथ उठाए गए हमारे कदम भी वे लोग गरीब विरोधी और किसान विरोधी कहकर प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन देश का गरीब और किसान समझदार है और हमारी नीयत और निष्ठा को जानता है। हम गरीबों और किसानों की आमदनी बढ़े, युवाओं को रोजगार मिले, इस दृष्टि से लगातार कदम उठा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि देश की जनता हमारे साथ खड़ी रहेगी। जहां तक विपक्ष के हमें गरीब विरोधी ठहराने का सवाल है तो उसके लिए मुझे इतना ही कहना है कि अगर वे लोग गरीबों के हितैषी थे तो देश में आज भी गरीबी क्यों है? किसने रोका था उन्हें गरीबी दूर करने से? हमारी रणनीति है गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की। हमें गरीबों को ही विश्वस्त साथी बना कर, कंधे से कंधा मिला करके गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़नी है और जीतनी है। हमारा विश्वास है कि गरीबी के खिलाफ ये लड़ाई जीतने के लिए गरीब ही सबसे शक्तिशाली माध्यम है और हमने उसी को अपना साथी बना कर गरीबी से मुक्ति की एक जंग आरंभ की है, जिसमें विजय निश्चित है।

आपकी सरकार ने वास्तव में गरीब, मध्य वर्ग और छोटे व्यापारियों के लिए 12 माह में कुछ किया है?

आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। आमतौर पर समाज का यह वर्ग सरकारों में अछूता रह जाता है। आज भारत के भविष्य को बनाने में मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। हमने उस पर ध्यान केंद्रित किया है। हमारी जितनी भी योजनाएं हैं, वो गरीबों, किसानों, मध्य वर्ग को समर्पित हैं। लोकसभा चुनाव के पहले एवं सरकार बनने के बाद हमारा एक ही मंत्र रहा है कि युवा वर्ग के लिए रोजगार बढ़ाना है। इसलिए हमने देश को वैश्विक निर्माण हब बनाने की दिशा में काम शुरू किया।

उद्योग जगत की उम्मीदें धूमिल होने लगी हैं। वे लोग मानने लगे हैं कि सरकार कुछ ज्यादा उनके लिए नहीं कर रही है।

-अपने पहले सवाल और इस सवाल को मिलाकर देखें तो खुद ही आरोपों में विरोधाभास नजर आएगा। एक तरफ विरोधियों का कहना है कि हम अमीरों के लिए काम करते हैं। और अमीर कहते हैं कि हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं। कॉरपोरेट घरानों की हमारे लिए यह शिकायत स्वाभाविक है। क्योंकि पिछली सरकार की तरह हम भाई-भतीजावाद के आधार पर प्रशासन नहीं चलाते। जो ईमानदारी से आगे बढ़ना चाहता है, बढ़ा बनना चाहता है, उसके लिए हमारी नीतियां स्पष्ट हैं। उसका लाभ कोई भी उठा सकता है। लेकिन अगर गलत रास्ते से किसी को कुछ पाना है तो यह इस सरकार में संभव नहीं है। शिकायत का एक कारण और भी है कि हमारे देशों में मजदूरों को उनके नसीब पर छोड़ दिया गया था। मजदूरों का कोई रखवाला नहीं था। मजदूरों के हित में कोई सरकार निर्णय करने को तैयार नहीं थी। हमने श्रमेव जयते का अभियान चलाया। श्रमिक के सम्मान को प्राथमिकता दी। मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की। मजदूरों को उनके हक का ईपीएफ का पैसा आवश्यक रूप से मिले, इसके लिए यूनिवर्सल एकाउंट नंबर (यूएएन) शुरू किया। अब स्वाभाविक है कि मजदूरों के लिए ये सब देना पड़ रहा है तो शिकायत रहेगी ही रहेगी।

क्या आपको लगता है कि औद्योगिक जगत की अनदेखी करके आप देश को आगे ले जा सकते हैं?

-हम मानते हैं कि भारत एक युवा देश है। रोजगार अधिकतम लोगों को कैसे मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। हम नए उद्योग भी चाहते हैं। जैसे कृषि क्षेत्र में मूल्यवृद्धि कैसे हो ताकि किसान को ज्यादा लाभ मिले। कृषि आधारित उद्योगों का जाल कैसे बने। दूसरा क्षेत्र है हमारी जो खनिज संपदा है, उसमें मूल्यवृद्धि कैसे हो? हम कच्चा माल विदेश भेजें कि हम कच्चे माल के आधार पर उद्योग लगाएं और सामान बनाकर दुनिया को भेजें। और हमारी खनिज संपदा से मूल्यवृद्धि हो। हमारी कोशिश है कि अब देश से लौह अयस्क बाहर नहीं जाना चाहिए। स्टील क्यों नहीं तैयार होना चाहिए। हमारा कॉटन तो विश्व बाजार में जाकर फैब्रिक और फैशन बनता है। हम इसे देश में क्यों नहीं कर सकते, जिससे देश के नौजवान को रोजगार मिले। हमने इस दिशा में पिछले 12 माह में बहुत प्रयास किए। व्यापार करने की सरलता के लिए बहुत काम हुआ है। जैसे कि

- कर पद्धति को सरल, स्थिर एवं पारदर्शी बनाया गया।
- बहुत से उत्पादों को इन्वर्टेड ड्यूटी के चलते देश में उत्पादन करने के बजाय आयात को बढ़ावा मिलता था, उसे हमने ठीक किया।
- व्यापार उद्योग शुरू करने के लिए विभिन्न विभागों से जो मंजूरियां लेनी पड़ती थीं, ऐसे 14 विषयों को ई-बिज के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर डाल दिया।
- बहुत से रक्षा उत्पादों को लाइसेंस लेने की अनिवार्यता से हटा दिया।
- औद्योगिक एवं शिपिंग लाइसेंसों की समयसीमा में बढ़ोतरी कर दी।
- भारत सरकार में निवेशकों को पूछने वाला अभी तक कोई नहीं होता था। हमने इनवेस्टर फैसिलिटेशन सेल बनाई है।
- लेबर से संबंधित बहुत-सी प्रक्रियाओं को सरल करके ऑनलाइन कर दिया है।

इन कदमों के नतीजे मिलने शुरू हुए?

-यह सब और ऐसे बहुत सारे कदम हमने इस सोच के साथ उठाए कि प्रशासनिक जटिलताओं के चलते हम कब तक पिछड़े रहेंगे। हमारा गरीब कब तक बेघर रहेगा। गरीब को घर देना ये राष्ट्र की जिम्मेदारी है। साथ-साथ घर देने का कार्यक्रम एक बड़ा बुनियादी ढांचा तैयार करने का काम भी है। अगर देश में करोड़ों मकान बनते हैं तो करोड़ों नौजवानों को रोजगार भी मिलता है। रेलवे एक गरीब व्यक्ति का साधन है। अगर गरीबों के लिए कुछ करना है तो रेलवे की उपेक्षा नहीं चल सकती, क्योंकि गरीब रेलवे में जाता है। हमारी रेल गंदी हो, रेल के समय का कोई ठिकाना न हो, ऐसा कब तक चलेगा? हम रेलवे को आधुनिक बनाना चाहते हैं। रेलवे की गति और इसके माध्यम से रोजगार और गरीब की सुविधा बढ़ाना चाहते हैं। इस तरह उद्योग की अनदेखी का सवाल ही नहीं उठता है। हम देश में उन उद्योगों का जाल बिछाना चाहते हैं जिनके कारण सर्वाधिक लोगों को रोजगार मिले। लेकिन रोजगार निर्माण की इस प्रक्रिया में उद्योग जगत के लिए बहुत-सी संभावनाएं खुलेंगी। पिछले 12 माह का प्रयास सार्थक रहा है। विदेशी निवेश 38.75 फीसद बढ़ा है। विदेशी निवेशकों और विदेशी संस्थाओं का दृष्टिकोण भारत के प्रति संपूर्ण रूप से बदल गया है। विश्वबैंक हो या आइएमएफ, सभी ने एक सुर में भारत की अर्थव्यवस्था की सही दिशा पर मुहर लगाई है। अभी कुछ ही दिन पहले वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर रेटिंग दी है। इन सारी बातों से स्वभाविक रूप से उद्योग जगत का मनोबल बढ़ा है। मुझे आशा है कि इस बदले हुए वातावरण का उद्योग जगत लाभ उठाएगा और देश में औद्योगिकीकरण एवं रोजगार निर्माण की दिशा में अपना कर्तव्य निभाएगा।

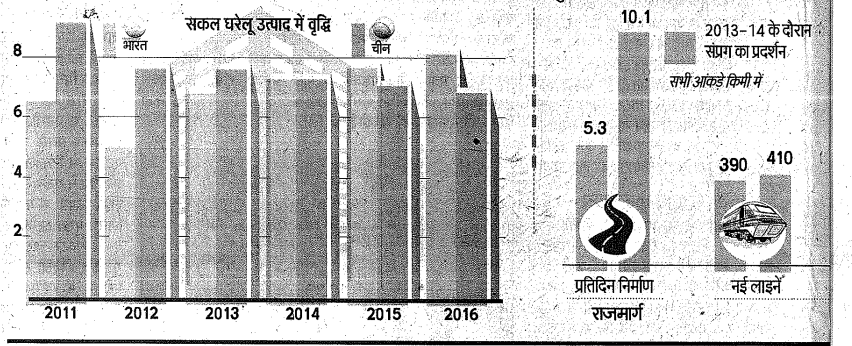

आपके कुछ सहयोगियों की ओर से हो रही बयानबाजी से आपको और पार्टी को नुकसान नहीं होगा?

-मानता हूं कि ऐसी बातों से देश का नुकसान होता है और इस प्रकार की बयानबाजी करने वालों को भी बचना चाहिए और देश के प्रबुद्धजनों को भी ऐसी बातों को तवज्जो देना बंद करना चाहिए। राष्ट्र के लिए सकारात्मक मुद्दों को ही हम सबको मिलकर बल देना चाहिए।

मेक इन इंडिया पर आपकी कल्पना क्या साकार होने की दिशा में कुछ आगे बढ़ी है?

-वैश्विक अर्थव्यवस्था का युग है। हर कोई अपना माल दुनिया में बेचना चाहता है। सवा सौ करोड़ का देश, दुनिया की नजरों में एक बहुत बड़ा बाजार है और ये स्वाभाविक भी है। क्या हमें, हमारे देश को दुनिया भर के लोगों को माल बेचने का एक बाजार बनाए रखना है? क्या हमें सिर्फ बनी-बनाई चीजों को खरीद कर गुजारा करना है? अगर उस रास्ते पर चलें तो भारत का कोई भविष्य है क्या? हमारी युवा पीढ़ी का कोई भविष्य बचेगा क्या? इसलिए हर देशवासी का सपना होना चाहिए कि हम हिंदुस्तान को बाजार नहीं मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। जिस देश के पास 80 करोड़ लोग 35 साल से कम उम्र के हों, उस देश का सामूहिक संकल्प होना चाहिए कि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी अपना रुतबा दिखाएंगे। इतने कम समय में पिछले साल की अपेक्षा विदेशी निवेश में 38.75 फीसद की वृद्धि इसका जीता-जागता उदाहरण है। पिछले 10 साल में भारत के बहुत से उद्योगपति और भारतीय कंपनियां, भारत के बाहर अपना पैर फैलाना जरूरी समझने लगी थीं। कुछ लोगों ने बाहर जाने का मन बना लिया था। आज बाहर जाने की वो भावना पूर्णतया खत्म हो गई है। इतना ही नहीं, भारत का अमूल्य शिक्षित मानवधन, जो भारत में कोई भविष्य न होने के कारण विदेशों में अपना करियर बनाने में लगा था वह भारत मां की होनहार संतान, भारत वापस आने के लिए उत्साहित नजर आते हैं। तो मेक इन इंडिया के जरिये भारत ने अपने सामर्थ्य का प्रभाव फैलाया है। जितना भारत में उसका प्रभाव है, उससे ज्यादा भारत के बाहर दिखता है।

भारत में कृषि संकट है। लेकिन आपकी सरकार ने कोई ठोस कदम उठाए हों, ऐसा नजर नहीं आता है?

-आपकी चिंता सही है कि बदलते हुए युग में कृषि को वैज्ञानिक और आधुनिक बनाने पर बल देना चाहिए था। समय रहते ये होना चाहिए था। परिवार बढ़ रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन टुकड़ों में बंटती चली जा रही है। लागत भी लगातार बढ़ रही है। एक समय था जब देश का किसान भारत के विकास में 60 फीसद योगदान करता था। आज उतने ही किसान सिर्फ 15 फीसद योगदान दे पा रहे हैं। खेत मजदूरों को तो कभी कोई पूछता भी नहीं है। इसलिए भारत में कृषि को आधुनिक बनाने की जरूरत है। वैज्ञानिक बनाने की आवश्यकता है। प्रति एकड़ उत्पादकता कैसे बढ़े? ताकि कम जमीन में भी किसान को आर्थिक रूप से लाभ मिले। हमने सोइल (जमीन) हेल्थ कार्ड लागू करने का काम

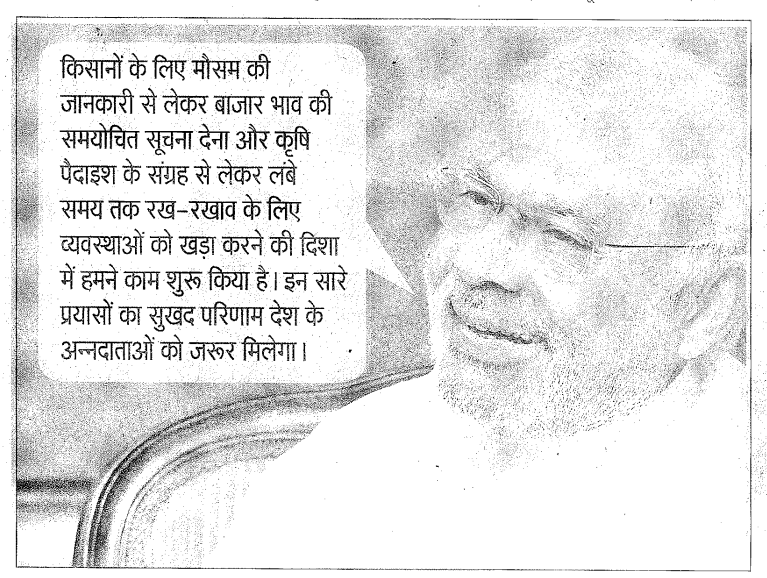

लेबर से संबंधित बहुत-सी प्रक्रियाओं को सरल करके ऑनलाइन कर दिया है।

फाइनेंशियल इनक्लूजन की बात हो- आज भी देश का एक बड़ा तबका जिसमें विद्यार्थी, किसान, मजदूर एवं व्यापारी शामिल हैं। गरीबों के लिए तो बैंक आज भी एक सपना है। बैंकिंग सुविधाओं से वंचित हैं। उन्हें उनके सामर्थ्य को साकार करने के लिए बैंकिंग सिस्टम में लाना जरूरी है।

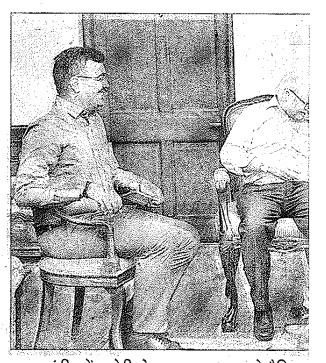

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल-जवाब करते दैनिक
एडिटर प्रशांत मिश्र और नेशनल चीफ आफ ब्यूरो राज

PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Dainik Jagran, Delhi
Monday 11th May 2015, Page: 8
Width: 39.45 cms, Height: 48.77 cms, a3, Ref: pmin.2015-05-11.34.44

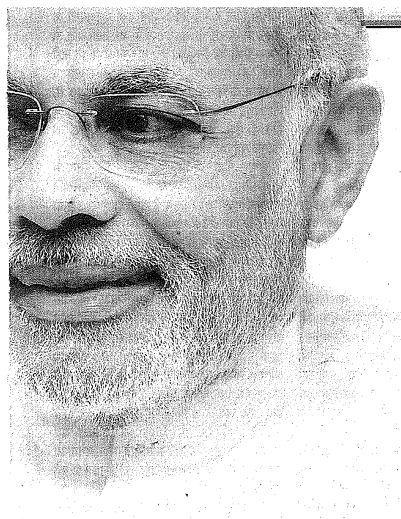

अगर वे लोग गरीबों के हितैषी थे तो देश में आज भी गरीबी क्यों है? किसने रोका था उन्हें गरीबी दूर करने से?

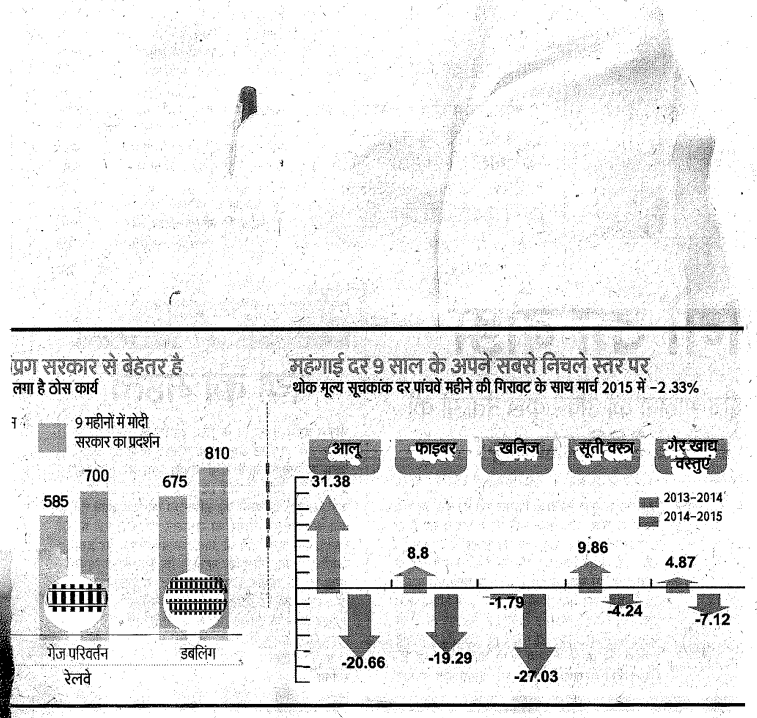

...प्रग सरकार से बेहतर है
...लगा है ठोस कार्य

महंगाई दर 9 साल के अपने सबसे निचले स्तर पर
थोक मूल्य सूचकांक दर पांचवें महीने की गिरावट के साथ मार्च 2015 में -2.33%

शुरू किया है, जिससे किसान के खेत में लागत कम हो और और उत्पादकता बढ़े। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के जरिए सिंचाई की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का प्रयास है। यूरिया में नीम की कोटिंग करने पर बल दिया है, जिससे किसानों को मिलने वाली यूरिया बिचौलिये न बेच खाएं।

किसानों के ऋण को लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं। साहूकारों से किसानों को मुक्ति कैसे मिलेगी?

-किसान को ऋण साहूकार से न लेना पड़े, उसका प्रबंध होना चाहिए। इसके लिए हमने जनधन योजना के तहत ओवड्राफ्ट की व्यवस्था की है। उसी प्रकार सहकारी बैंकों के कामकाज में सुधार करने का काम हमने हाथ में लिया है। फसलों की बीमा योजनाओं को और वैज्ञानिक व सुदृढ़ बनाने की व्यवस्था हम कर रहे हैं। किसानों को मिलने वाले ऋण के लक्ष्य में हमने अपने उत्तरोत्तर दो बजट में वृद्धि की है। किसान संपूर्ण रूप से देश की बैंकिंग व्यवस्था के साथ जुड़ें, इस दिशा में हम निरंतर प्रयासरत हैं।

एमएसपी के संबंध में जो कुछ हो रहा है, उससे आप संतुष्ट हैं क्या?

-यहां आने के बाद मैंने देखा कि ये न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) जो कि हर किसान के मुंह से सुनने को मिलता है, उसके निर्धारण की कोई वैज्ञानिक पद्धति नहीं है। हर राज्य का अपना तौर-तरीका है। और मैं तो जानकर हैरान हुआ कि पूर्वी हिंदुस्तान में तो इसकी काफी उपेक्षा है। सबसे पहले एमएसपी का लाभ अधिकतम किसान को कैसे मिले? सभी राज्यों में कैसे एक सूत्रता हो और समय रहते हस्तक्षेप कैसे हो? ये प्राथमिक बातें हमें ही करनी पड़ेंगी, ऐसा मुझे लगता है।

पिछले वर्ष कॉटन की कीमतों को लेकर चिंता थी। हमने बहुत बड़े पैमाने पर कॉटन की खरीद एमएसपी के आधार पर कराई। पूर्वी भारत में होने वाले अन्न उत्पादन को भी एमएसपी का लाभ मिले, उसके लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं। उसी प्रकार से एमएसपी में अन्न लेने के बाद, धान खरीदने के बाद उसका प्रबंधन भी बड़ी मात्रा में करना पड़ेगा। किसान को अगर अपनी फसल रखने की उचित व्यवस्था मिल जाए तो सस्ते दाम पर अपना माल बेचने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। इन सारे विषयों पर हम गंभीरता से एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं, जिसका लाभ आने वाले दिनों में मिलेगा।

प्रधानमंत्री पद के दायित्व के साथ भाजपा संगठन से कितना और कैसा संबंध रख पाते हैं?

-जहां तक संगठन का सवाल है, मैं पहले भी दिल्ली स्तर पर सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ था, यह मेरे लिए नया नहीं था। संगठन का समर्थन मुझे पहले भी था और आज भी है। संगठन और देश का समर्थन न होता मैं आज यहां कैसे होता?

आप दूसरी हरित क्रांति की बात करते हैं, आपकी क्या कल्पना है?

-पहली हरित क्रांति में भी पूर्वी भारत एक प्रकार से अछूता रह गया। जहां पानी बहुत है, जमीन भी विपुल है। औद्योगिकीकरण नहीं हुआ है। मेहनतकश किसान हैं। हमारी सरकार इस पूर्वी भारत में आर्थिक विकास के लिए कृषि पर सर्वाधिक बल देना चाहती है। चाहे ये पूर्वी राज्य उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, ओडिशा, पश्चिम बंगाल या उत्तर-पूर्व के राज्य हों। ये सब राज्य दूसरी हरित क्रांति का नेतृत्व करेंगे।

पिछले माह बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि से फसलों को बहुत नुकसान हुआ। आपकी सरकार राहत के लिए क्या कर पाई?

-हमारे देश के किसी न किसी हिस्से में हर साल प्राकृतिक आपदा से किसानों का नुकसान होता रहा है। ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के समय पहले बातों से ज्यादा किसानों को कुछ नहीं मिलता था। मैं स्वयं गुजरात में मुख्यमंत्री था। ऐसी अनेक आपदाएं हमने झेलीं, लेकिन कभी केंद्र सरकार से कोई विशेष लाभ हम किसानों के लिए नहीं ले पाए थे। जबकि इस बार इस आपदा के समय सरकार की सक्रियता, मंत्रियों की आपदाग्रस्त किसानों से सीधी बातचीत, मंत्रियों का क्षेत्रभ्रमण, सरकारी अधिकारियों की टोलियों को पहुंचाने का काम और सर्वेक्षण का काम तेज गति से हुआ है। राज्यों की वर्षों पुरानी मांगों पर हमने नीतिगत निर्णय कर लिए हैं। सरकार ने प्रभावित किसानों की मदद के लिए अभी तक के नियमों में बदलाव किया है। उन किसानों को भी राहत दी जा रही है, जिनका नुकसान 33 फीसद था। अभी तक यह मापदंड 50 प्रतिशत तक था। इतना ही नहीं, हमने अभी तक की व्यवस्था परिवर्तन करके किसानों को प्रति हेक्टेयर मिलने वाली सहायता की राशि डेढ़ गुणा कर दी है। वर्षा एवं ओले से नुकसानग्रस्त फसलों से पैदा होने वाले अनाज की गुणवत्ता में कोई क्षति हो तो उसकी खरीद भी एमएसपी पर ही की जाए। इसके लिए अनाज की औसत गुणवत्ता के मानकों को शिथिल किया गया है। जिन भी राज्यों ने भारत सरकार को प्रतिवेदन दिए हैं, वहां भारत सरकार की टीम जा चुकी है और अग्रिम कार्रवाई हो रही है।

आपने कहा था कि मनरेगा को कमजोर नहीं किया जाएगा, लेकिन कार्यदिवस घटने के बाद अब मनरेगा को ले कर आशंका गहरा रही है?

-हमने मनरेगा बंद करने की अफवाहों का खंडन किया है। हम इसे चालू रखने वाले हैं। बजट में इसके लिए संपूर्ण प्रावधान किया गया है। कार्यदिवस घटने या बढ़ने की समस्या सरकार से संबंधित नहीं है, जिसे भी मनरेगा के तहत रोजगार के लिए काम की जरूरत होगी, उसके लिए विकल्प खुले हैं।

इस योजना के तहत मेरा स्वप्न है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय तक टिकने वाली जनउपयोगी सुविधाएं खड़ी हों। जैसे कि- किसानों की मदद हो सके, कृषि की उत्पादकता बढ़े और जल प्रबंधन हो। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में वनीकरण को बढ़ावा देकर हरियाली क्षेत्र बढ़ाया जाए। तभी किसानों को वास्तविक लाभ मिलेगा, गांव में रोजगार बढ़ेगा और गांवों की लंबे समय की समृद्धि और खुशहाली के रास्ते खुलेंगे।

राज्यसभा सरकार के लिए परेशानी का सबब बन गई है? सरकार कई विधेयक पारित कराने में सफल तो रही है, लेकिन फ्लोर प्रबंधन में क्या कुछ खामी नजर नहीं आती?

-मैं समझता हूं कि देशहित में विचार करने वाले नागरिकों में यह विचार आना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन इसके लिए सरकार को कठघरे में रखने की जो परंपरा बनी है वह उचित नहीं है। हम सब भली भांति जानते हैं कि राज्यसभा में हमारा बहुमत नहीं है। हम यह भी जानते हैं कि राज्यसभा में जो दल हैं उनके अपने-अपने राजनीतिक विचार हैं। और इसीलिए सरकार की कोशिश है सबको साथ लेकर चलना। रास्ते निकालना और देशहित में आगे बढ़ना। मुझे खुशी है कि इतने कम समय में 40 से अधिक विधेयक हम पारित करा चुके हैं। और इसके लिए विपक्ष का भी धन्यवाद। हम सबका प्रयास रहे कि लोकसभा में जिन भावनाओं को प्रकट किया गया हो, राज्यसभा भी उन भावनाओं का आदर करते हुए देशहित के निर्णयों को आगे बढ़ाए। इन दिनों एक बहुत ही आनंददायक काम हुआ है। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समझौते को संसद में सर्वसम्मति से समर्थन मिला। उसके लिए मैं सभी दलों का आभार व्यक्त करता हूं। सात दशकों से यह सीमा विवाद था, हमने शांति और सौहार्द से इसको हल किया। सीमा विवाद भी शांति से हल हो सकते हैं। यह संकेत हमने भारत को ही नहीं, पूरी दुनिया को दिया है। हमें विश्वास है कि इस समझौते से अंतरराष्ट्रीय सीमा पर शांति और स्थिरता का माहौल कायम करने में सहयोग मिलेगा।

क्या आपको कई बार ऐसा नहीं लगता कि सरकार की तैयारी विपक्ष के सामने कमतर पड़ जाती है?

-मैं समझता हूं की शालीनता, भद्रता, विवेक, नम्रता इन चीजों को कमजोरी नहीं मानना चाहिए। हम तत्वतः मानते हैं कि अगर जनता ने हमें शासन की बागडोर दी है तो सबसे अधिक नम्रता और शालीनता हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए कभी सदन में हम संख्या बल में पीछे भी रह जाएं तो मैं इसे डिस्क्रेडिट नहीं मानता। हम ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देते हैं। जहां तक सदन चलाने का सवाल है तो शासक दल के नाते हमारी भूमिका सबको साथ लेकर चलने की होनी चाहिए। उसी का परिणाम हुआ कि चालीस बिल इतने कम समय में पारित हो गए। बांग्लादेश सीमा विधेयक का निर्णय ऐतिहासिक है। इसलिए मेरे तराजू अलग हैं। सदन में जीत या हार का मुद्दा ही नहीं होता है। विवादों और भाषणों में, किसके आरोप अच्छे, किसके कमेंट शार्प थे, इससे ज्यादा जरूरी है कि लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए और लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा काम किया जा सके।

फिर भी सदन में आपको कुछ रिक्तता महसूस नहीं होती?

-मुझे जो कमी महसूस होती है वह व्यंग्य और विनोद की होती है। संसदीय लोकतंत्र की जीवंतता के लिए यह जरूरी है। यदि अंतरराष्ट्रीय राजनीति या विदेश नीति पर आएं तो 12 माह से कम समय में 16 देशों की यात्रा... (हाथ के इशारे से रोककर बोलते हैं..) जब भी मेरी आलोचना होती थी, उसमें दो बातों में बिल्कुल सच्चाई थी। एक आलोचना कि मोदी को गुजरात के बाहर कौन जानता है? दूसरी आलोचना यह होती थी कि मोदी विदेश को क्या समझता है? विदेश नीति को लेकर मेरा मजाक उड़ाया जाता था। मेरे बारे में बहुत ही मजाकिया बयान आते थे। मगर जब सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में मैंने सार्क देशों को बुलाने का निर्णय किया तो विदेश विषयों के जितने पंडित थे उनको आश्चर्य हुआ। लेकिन मैं एक बात का अनुभव करता था कि यह कैसा मनोविज्ञान था दिल्ली का, जिसमें राज्यों को सहभागी मानने का स्वभाव नहीं था। सबको समझना होगा कि ये देश एक पिलर से खड़ा नहीं हो सकता है। वन प्लस 29 पिलर से ही देश खड़ा हो सकता है।

चुनाव की दृष्टि से अगली चुनौती बिहार है। आपकी रणनीति क्या होगी?

-राजनीतिक दलों के लिए हर चुनाव चुनौती होती है और जनता के पास जाकर लोकशिक्षा करने का अवसर भी होता है। देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपार विश्वास जताया है। भरपूर आशीर्वाद दिया है। आने वाले चुनाव में भी यह सिलसिला बरकरार रहेगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है।

आप कुछ दिनों पहले तीन देशों की यात्रा से लौटे हैं। इसके पहले दर्जनों देशों के साथ संवाद प्रक्रिया तेज हुई। इस दिशा में आपकी रणनीति क्या है?

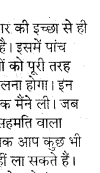

-हम जानते हैं कि 21 वीं सदी की शुरुआत में पूरे विश्व में भारत के प्रति बहुत आशाएं थीं। लेकिन गत एक दशक में पूरे विश्व में भारत के प्रति निराशा का माहौल बन गया। 21वीं सदी के आरंभ में पांच तेजी से विकास करने वाले देशों के बारे में ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन, दक्षिण अफ्रीका) की कल्पना आई। ऐसा माना जाता था कि इस सदी में ये देश ड्राइव करेंगे। देखते ही देखते विश्व में चर्चा होने लगी कि ब्रिक्स में इंडिया कमजोर पड़ रहा है। ब्रिक्स का कंसेप्ट ही डांवाडोल हो गया। ऐसी स्थिति में मेरी सरकार की जिम्मेवारी बनी। मैं जानता था कि चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। विश्व मेरे लिए भी नया था। विश्व में भारत के लिए नजरिया बदले, ये अनिवार्य था और इसके लिए मैंने चुनौती को स्वीकार किया- खुद जाऊंगा।

दुनिया को भारत के प्रति, इसकी शक्ति के संबंध में, भारत की संभावनाओं के संबंध में संवाद करूंगा, बराबरी से बात करूंगा। आज मुझे इस बात का संतोष है कि विश्व में भारत की तरफ देखने का नजरिया बहुत ही सकारात्मक हुआ है।

पड़ोसी देश आपकी प्राथमिकता में रहे हैं। दौरे भी हुए लेकिन पाकिस्तान छूट गया। पाकिस्तान की ओर से आप किस माहौल का इंतजार करेंगे? आप की उम्मीदें क्या हैं?

-पाकिस्तान से एकमात्र उम्मीद है कि वह शांति एवं अहिंसा के मार्ग पर चले, बाकी कोई अड़चन नहीं है। हिंसा का मार्ग न तो उनके लिए लाभदायक है और न हमारे लिए।

जम्मू-कश्मीर में भाजपा-पीडीपी गठबंधन सरकार से आप कितने संतुष्ट हैं?

-सवा सौ करोड़ देशवासियों के दिल में स्वयं के राज्य के प्रति जितना लगाव है, उससे ज्यादा हर हिंदुस्तानी का कश्मीर के प्रति लगाव है। इस सच्चाई को स्वीकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक नए प्रयोग के लिए साहस किया। राजनीतिक विचारधारा की दृष्टि से देखें तो पीडीपी और भाजपा के बीच उत्तर और दक्षिण ध्रुव जितना अंतर है। जम्मू-कश्मीर की जनता ने दोनों दलों को साथ चलने के लिए जनादेश दिया। और जनादेश का सम्मान करते हुए दोनों दल अपने-अपने राजनीतिक विचारों को पीछे रखते हुए राज्य के विकास के एजेंडे को लेकर साथ आए हैं। भारत के अन्य राज्यों की तरह जम्मू-कश्मीर का विकास हो, वहां के नौजवानों को रोजगार के अवसर मिलें, पहले की तरह देश-विदेश के टूरिस्ट आने लगें, इसके लिए जो भी कदम उठाने चाहिए, उसका प्रयास चल रहा है। हम आशा करते हैं कि ये प्रयोग सफल हो और करोड़ों देशवासियों की आशाएं- आकांक्षाएं पूरी हों।

हाल के दिनों में अल्पसंख्यक समाज के बहुत सारे प्रतिनिधि आपसे मिल रहे हैं। इसे कैसे देखा जाए?

-न तो ये राजनीति है और न ही रणनीति है। अगर है तो सिर्फ राष्ट्रनीति है। इस देश के हर नागरिक का इस सरकार और सरकार के मुखिया के नाते मुझ पर समान अधिकार है। किसी भी संप्रदाय के हों, कोई भी जाति हो, किसी भी भाषा के लोग हों, गरीब हों या अनपढ़ हों, हरेक का सरकार पर पूरा हक है। और अपनी बात बताने का भी पूरा हक है। मेरी ये जिम्मेवारी है कि मुझे समाज के सभी तबके के लोगों से मिलना भी चाहिए और उनको सुनना-समझना भी चाहिए। उनके सुझावों पर ध्यान देना चाहिए और यह प्रयास मैं निरंतर करता रहता हूं।

आपकी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। इसका कारण क्या मानते हैं?

-मैं भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान टीम को और उनके अध्यक्ष अमित भाई शाह का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा अभियान चलाया। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की जिम्मेवारी है कि वे नागरिकों को राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित करते रहें, निरंतर करते रहें, इससे लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होती हैं। सदस्यता अभियान भी उसी दिशा में एक अहम कदम है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते इससे आनंददायक तो कुछ हो नहीं सकता है कि मेरी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। दुर्भाग्य से देश में कई राजनीतिक दल पारिवारिक पार्टी बन गए हैं। आजादी का आंदोलन चलाने वाली कांग्रेस जैसी महान पार्टी भी दुर्भाग्य से आज परिवारवाद में सिकुड़ती चली जा रही है।

गुजरात से दिल्ली... अब एक साल बाद दोनों जगह की संस्कृति और आबो-हवा में क्या फर्क महसूस कर रहे हैं और दिनचर्या किस तरह बदली है?

-(ठहाके के साथ) मेरी दिनचर्या में कोई फर्क नहीं है। मैं पहले की तरह वही पांच बजे उठता हूं। विदेश जाता हूं तब भी उतने बजे ही उठता हूं। लगता है कि मेरा बाडी क्लाक ही ऐसे वर्क करता है। वर्कहोलिक हूं, काम बहुत करता हूं। बाकी रही फर्क की बात तो...मुझे इन चीजों से रू-ब-रू होने का अवसर ही नहीं मिलता है। वहां भी मेरा जेलखाना था, यहां भी मेरा जेलखाना है। अब, उस प्रकार से सहज जीवन से रू-ब-रू होना, फिर जांचना संभव नहीं होता है। थोड़ा-बहुत होता है तो किसी शादी-ब्याह में चला जाता हूं। तो वहां भी मैं बहुत सहज नहीं होता हूं। जाता हूं और चला आता हूं।

विदेश में छिपाए गए काले धन को स्वदेश लाने की मुहिम कहां तक पहुंची, ठोस परिणाम कब तक दिखने लगेंगे?

-सारा देश जानता है कि काले धन की जब भी बात आती थी तो पुरानी सरकारें मुंह छिपाती थीं। संसद तक में जवाब नहीं दिया जाता था। और उसके कारण देश में जन सामान्य के मन में स्थिर हो गया है कि भारत में से चुराया हुआ धन, काला धन, विदेशी बैंकों में मुट्ठी भर लोगों ने कब्जा करके रखा हुआ है। देशहित के प्रति संवेदनशील भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसी स्थिति में मौन रहना उचित नहीं है और इसलिए हमने मुहिम चलाई। चुनाव के समय हमने कहा कि हम कालेधन को वापस लाने का हर संभव प्रयास करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद कांग्रेस ने तीन साल तक एसआइटी नहीं बनाई। हमने आते ही पहली कैबिनेट में पहला निर्णय किया और आज वो एसआइटी सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन में कालेधन को वापस लाने की दिशा में काम कर रही है। हमने काला धन वापस लाने के लिए दुनिया के देशों से भी मदद मांगी और जी-20 में हमने प्रस्ताव भी पारित कराया। अब वर्तमान में संसद में भी कालेधन के खिलाफ कठोर कानून बना रहे हैं। जिससे विदेशों में छिपा हुआ काला धन वापस आने की संभावना भी बढ़ेगी और भविष्य में भी लोग डरेंगे।

दिल्ली अब आपके लिए कितनी पुरानी या नई रह गई है?

-दिल्ली का स्वभाव हो या गठबंधन की सरकारों का स्वभाव हो या फिर पूर्ण बहुमत का अभाव हो, हर विभाग अपने में सरकार बन गया था। अब ये आते ही जेहन में आ गया। सरकार एक होती है सारे अंग-उपांग होते हैं। सारे भागों को मिलकर चलना होता है। जहां तक दिल्ली स्थित भारत सरकार का सवाल है तो उसमें हमने पिछले 12 महीनों में कार्य संस्कृति बदलने के लिए बहुत काम किया है और अनुभव भी अच्छे रहे हैं।

साथ ही पहले यहां सब कुछ एक खोल के अंदर चलता था और फाइलों को एक खोल से दूसरे खोल तक जाने में महीनों लग जाते थे। इससे मुक्ति दिलाकर एकरसता और सौहार्द से भरा माहौल बनाने का प्रयास किया। काफी हद तक सफलता मिली है। आज मिल-बैठकर तेजी से निर्णय हो रहे हैं। मंत्रालयों और विभागों ने देश के प्रति समर्पण की भावना से काम करना शुरू किया है। सरकार अब एक आर्गेनिक एंटिटी की तरह दिखनी शुरू हुई है। इसके अच्छे परिणाम देश को मिलेंगे। यह मेरे लिए काफी संतोष का विषय है।

मुझे गंगा ने बुलाया है? आपका यह वाक्य देशवासियों के जेहन में ताजा है। काशी के घाटों की साफ-सफाई पर जरूर प्रभाव पड़ा है, लेकिन निर्मल और पावन गंगा की दिशा में कब तक कुछ दिखना शुरू होगा?

-(सहमति में सिर हिलाते हुए) देखिए, ये गंगा स्वच्छता का विषय 84 से चल रहा है। हजारों करोड़ रुपये खर्च किए गए। लेकिन परिणाम नहीं निकले। मुझे पहले यह खोजना है कि गलती क्या हुई और बर्बादी क्या हुई। अगर मैं भी वही गलती दोहराऊंगा तो फिर करोड़ों रुपये बर्बाद हो जाएंगे। दूसरा, मेरा मत है कि हमें दुनिया की सर्वश्रेष्ठ तकनीक लानी चाहिए। लगातार हम प्रयास कर रहे हैं।

तीसरा, यह केंद्र सरकार की इच्छा से ही होने वाला कार्यक्रम नहीं है। इसमें पांच राज्य आते हैं। पांचों राज्यों को पूरी तरह कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। इन सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक मैंने ली। जब तक इन सभी राज्यों की सहमति वाला निर्णय नहीं होता है, तब तक आप कुछ भी चीज थोपकर परिणाम नहीं ला सकते हैं। मुझे विश्वास है कि हमने जो मनोमंथन किया और रास्ता ढूंढा है, उससे हम पिछले 30 साल में गंगा के लिए जो रुपये और समय बर्बाद करते गए, उससे बाहर निकलेंगे।

गरीब, मजदूर, महिलाओं एवं वृद्धों को आर्थिक सुरक्षा देनी है। प्रधानमंत्री जन-धन योजना उनको समर्पित है। मात्र 5 माह के अंदर 14 करोड़ से ज्यादा परिवारों के बैंक एकाउंट खुल चुके हैं।

छोटे व्यापारियों एवं उद्यमियों के लिए बैंक लोन की कोई सुविधा नहीं थी। हमने मुद्रा बैंक शुरू किया है1

गरीब हो या निम्न मध्य वर्ग या नया मध्य वर्ग- सब लोग सिर के ऊपर छत चाहते हैं। देश के ऐसे लगभग 50 लाख परिवार आवास से वंचित हैं। हमने सबके लिए आवास का बड़ा काम हाथ में लिया है।

किसानों को सोइल हेल्थ कार्ड देने की बात हो या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत खेत-खेत में पानी पहुंचाने की बात हो- हम इस पर काम कर रहे हैं।

गरीबों एवं निम्न मध्य वर्ग के परिवार में कोई बीमार पड़ जाए तो उसकी दवा में जो खर्च होता है, उससे उस परिवार का पूरा आर्थिक ढांचा चरमरा जाता है। उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि दुर्घटना के चलते यदि व्यक्ति काम करने लायक न रहे या मौत हो जाए तो उस परिवार का भविष्य अंधकारमय हो जाता है। हमने सामाजिक सुरक्षा की नई योजनाएं दाखिल कीं जिसमें जीवन बीमा से लेकर दुर्घटना बीमा का कवच बहुत ही सामान्य प्रीमियम के साथ मिलता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल-जवाब करते दैनिक जागरण के सीनियर एक्जिक्यूटिव एडिटर प्रशांत मिश्र और नेशनल चीफ आफ ब्यूरो राजकिशोर

कोई भी भारतीय इस बात पर गर्व कर सकता है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की तरफ से अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के लिए प्रस्ताव रखा गया और इतिहास में पहली बार 177 देशों ने उसको समर्थन किया और सिर्फ सौ दिन में ही यह प्रस्ताव पारित हो गया।

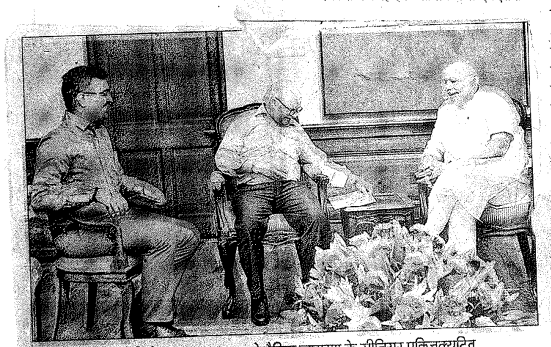

हमें जन-जन तक शिक्षा पहुंचानी है। स्कूलों में शौचालय की सुविधा के साथ-साथ प्रौद्योगिकी का उपयोग करके शिक्षा के फैलाव एवं स्तर को सुधारने में हम लगे हैं।

मेक इन इंडिया 80 करोड़ नौजवानों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। बहुत कम समय में विश्व ने इस बात को माना भी है। अभी मैं फ्रांस, जर्मनी, कनाडा गया तो जितनी बार मैंने मेक इन इंडिया कहा, उससे ज्यादा वहां के उद्योगपति और उन देशों के राजनेता मेक इन इंडिया बोल रहे थे।

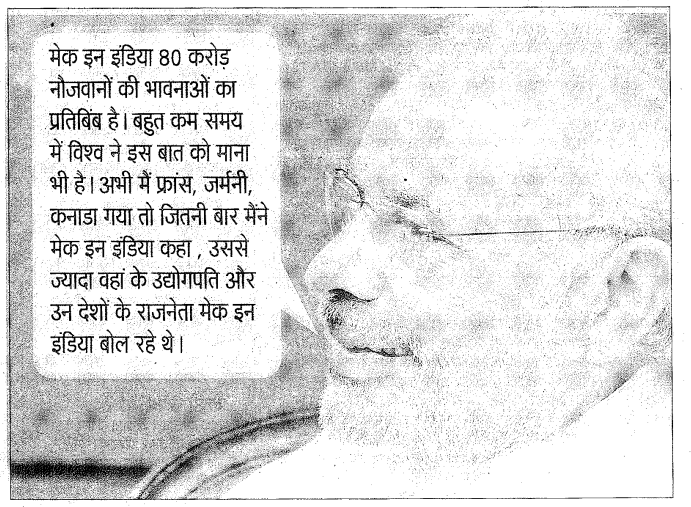

PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Rashtriya Sahara, Delhi
Monday 11th May 2015, Page: 12
Width: 7.71 cms, Height: 9.24 cms, a4, Ref: pmin.2015-05-11.40.182

खादी की बिक्री में 60 फीसद का इजाफा

नई दिल्ली (वि.)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' में देशवासियों से कम से कम एक खादी वस्त्र खरीदने की अपील एवं केंद्रीय एमएसएमई मंत्री कलराज मिश्र के मार्गदर्शन में खादी ग्रामोद्योग भवन, कनाट प्लेस नई दिल्ली के स्थापना वर्ष पर एक

विशेष 'कुर्ता पायजामा प्रदर्शनी' का आयोजन किया गया जिससे खादी ग्रामोद्योग भवन की कुल बिक्री में अप्रैल 2014 की तुलना में 60 फीसद तक की वृद्धि दर्ज हुई है। रेडिमेड कपड़ों की बिक्री में 86 फीसद तक की रिकार्ड वृद्धि दर्ज की गई। खादी ग्रामोद्योग भवन के डिप्टी सीईओ केएस राव ने बताया कि युवाओं को ध्यान में रखते हुए खादी ग्रामोद्योग भवन में एनआईएफटी के छात्रों द्वारा डिजाइन किए खादी के वस्त्र विशेष रूप से तैयार किए गए हैं जिन्हें बिक्री के लिए प्रदर्शनी में विशेष तौर पर रखा गया है। खादी ग्रामोद्योग आयोग के सीईओ अरुण कुमार झा ने बताया कि खादी त्वचानुकूल एवं मौसम के अनुकूल वस्त्र है। कनाट प्लेस स्थित खादी ग्रामोद्योग भवन में 16 मई, 2015 से एक 'खादी समर कलेक्शन' परिधानों पर विशेष प्रदर्शनी लगाई जाएगी।

PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Hindu, Delhi
Monday 11th May 2015, Page: 13
Width: 21.83 cms, Height: 23.22 cms, a3, Ref: pmin.2015-05-11.43.102

ORGANISED RETAIL IN INDIA

- Highly competitive environment in retail sector pushing consolidation to create larger players
- Retailers forced to embrace e-commerce with majority of them having already done so
- Now newer players are emerging and regional players are getting stronger

REVAMPING FOR GROWTH

The consolidation happening in the industry follows some acceptance of the fact that 100 per cent foreign direct investment will not happen and it is left to the domestic players to grow their share

Ramnath Subbu

India's fragmented retail sector is in a churn and two major developments last week point to the consolidation currently underway. The churn has been precipitated by the fragmented nature of the industry, the need to develop scalable models to stay ahead as also the challenges posed by the growing e-commerce industry. Aditya Birla group announced the consolidation of all its branded apparel businesses under one company Aditya Birla Fashion and Retail, which will be India's largest pure play fashion and Lifestyle company with a network of more than 1,800 stores spanning five million sq. ft. The company also plans to add another 200 stores this year.

"FOR LIFESTYLE BRANDS IN E-COMMERCE, THE NEED OF THE HOUR IS TO PROTECT THE BRAND AND ENSURE THAT THERE IS NO INDISCRIMINATE DISCOUNTING

— KUMAR RAJAGOPALAN,
CEO, Retailers Association of India (RAI)

This was immediately followed by Bharti Retail announcing plans to merge with the retail operations of Future Retail. As per the arrangement, Future Retail will demerge its retail operations into Bharti Retail, which will demerge its retail infrastructure into Future Retail.

Kumar Rajagopalan, CEO, Retailers Association of India (RAI) "The brick and mortar (B&M) retailers have to do things to achieve scale and amid increasing consumption and competition, there is a scramble among serious players to increase scale through M&A."

There is likely to be more M&A activity in the apparel segment but it has more to do with brand acquisition than with retail points," Arvind Singhal, Chairman, Technopak Advisors, a leading retail consultancy said.

The highly competitive environment is pushing consolidation to create larger players. Increasing consumption amid heavy competition demands M&A activity to create larger players to achieve financial size and scale.

The extent of fragmentation in the industry can be gauged by the fact that the largest player Reliance Retail with a turnover in the region of Rs.18,000 crore or $3 billion, accounts for a meagre share of the industry, which is estimated at $540 billion. This is likely to grow to $1 trillion by 2020, a report by Boston Consulting Group said. There are a few majors such as Reliance, Future-Bharti and Aditya Birla Group. Although the Birlas have moved with alacrity to consolidate their apparel business, the performance of the pure-play retail chain stores under 'More' requires attention according to sector analysts.

Now newer players are emerging and regional players are getting stronger. It seems like there are fewer scale players and the attention is shifting to region-specific players for M&As.

"There are not that many large players in the retail sector and those remaining are regional majors such as Spencers," said Rachna Nath, Leader – Retail, PwC India. The consolidation happening in the industry follows some acceptance of the fact that 100 per cent foreign direct investment (FDI) will not happen and it is left to the domestic players to grow the pie and expand their share.

Under the current rules, while 100 per cent foreign ownership is allowed in cash-and-carry trade, or wholesale trade, as well as single-brand retail, there is a cap of 51 per cent in multi-brand retail. Also, it has been left for each state to decide whether it wants foreign ownership of multi-brand retail stores or not.

In its keenness to protect interests of the smaller, unorganised trade, the government has been sending strong signals about its opposition to mega international retailers coming in. "The government has been too focused on the ownership issue and has displayed a misplaced understanding of the sector," Mr. Singhal said. "Pure play multinational retailers are avoiding India due to the government's ambivalent attitude to FDI and it has been sending unwelcome signals. They are anyway already selling their products through e-commerce which is in fact an area that the government does not know how to handle," Mr. Rajagopalan said.

E-commerce or e-tailing is the recent paradigm that retailers have had to also confront and already 75 per cent of retailers have adopted e-commerce in some form and globally, retailing has already graduated to a multi-channel, omni-channel retail industry.

"E-commerce has emerged out of nowhere and forced retailers to adapt. However, its growth has been predicated on excessive discounting which is not viable in the long term," Mr. Singhal said.

"For lifestyle brands in e-commerce, the need of the hour is to protect the brand and ensure that there is no indiscriminate discounting," Mr. Rajagopalan said. "This is why leading luxury and high-end players globally as well as several leading retailers here do not offer discounts on their websites."

The margins of retailers have been impacted and although it is expected that discounting will continue for 12-18 months, the players are moving beyond discounts and thinking about building customer loyalty.

"Today, as competition intensifies and consolidation sets in, retailers are being forced to adapt to the e-commerce opportunity," Mr. Rajagopalan said. "Besides having to adopt an omni channel strategy using offline and online channels to offer a seamless and unified customer experience in order to stay relevant."

ramnathsubbu.r@thehindu.co.in

ILLUSTRATION: PRATHAP RAVISHANKAR